नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Thursday 1st January 2026 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 246 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

दुनिया और दिल्ली-NCR में नए साल 2026 का धूमधाम से स्वागत

देश और दुनिया भर में नया साल 2026 उत्साह, आतिशबाजी और रंगीन जश्न के साथ मनाया जा रहा है। Kiribati और न्यूज़ीलैंड जैसे प्रांतों से शुरुआत होने वाली यह उत्सव लहर अब एशिया, यूरोप और अमेरिका तक फैल चुकी है, जहाँ प्रसिद्ध लोकेशन पर शानदार आतिशबाजी, संगीत और रौशनी शो ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया है। दुबई में बुर्ज खलीफा पर लाइट और लेजर शो तथा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 'बॉल ड्रॉप' कार्यक्रम ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली में भी लोग सड़कों, क्लबों और होटलों में जमकर जश्न मना रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएँ दीं।

दिल्ली-NCR में युवाओं ने नए साल का स्वागत जोश के साथ किया। हौज खास विलेज, महरौली और छतरपुर जैसे इलाकों में युवा गीत-संगीत पर नाचे और रात बारह बजे से आतिशबाजी से वातावरण गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर तैनाती की और यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की। होटल, मॉल और रेस्टोरेंट्स भी उत्सव से गुलजार रहे।

साल 2025 | में अमेरिका से कैसा रहा भारत का रिश्ता,

साल 2025 में अमेरिका से कैसा रहा भारत का रिश्ता, US एबेंसी ने एक वीडियो में बता दी पूरी कहानी, देख लीजिए

नई दिल्ली : भारत में अमेरिकी दूतावास ने साल के आखिर में एक सालभर के सफर को याद किया। इसमें 2025 में भारत-अमेरिका संबंधों को आकार देने वाले खास पलों को हाईलाइट किया गया है। दूतावास ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच 'और भी मजबूत' संबंधों वाले एक और साल का इंतजार कर रहा है। X पर एक पोस्ट में, US दूतावास ने लिखा कि नया साल आ रहा है... लेकिन पहले, रिवाइंड! इस साल US-इंडिया पार्टनरशिप को आकार देने वाले टॉप पलों पर एक नज़र डालें, जबकि हम और भी मजबूत US-इंडिया संबंधों के एक और साल के लिए तैयार हो रहे हैं।

दोनों देशों के बीच रिश्तों की अहमियत

इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी है। वीडियो में पिछले एक साल में हुई अहम डिप्लोमैटिक मुलाकातों और समझौतों को दिखाया गया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 की शुरुआत में वॉशिंगटन दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के विजुअल्स शामिल हैं।

दोनों नेताओं को वाइट हाउस में बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। ये इस बात पर जोर देता है कि मुश्किल ग्लोबल माहौल के बावजूद दोनों पक्षों ने हाई-लेवल बातचीत को कितनी अहमियत दी।

भारत के साथ डिफेंस संबंधों की मजबूती

इस मोंटाज में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात भी दिखाई गई है। दिखाए गए मुख्य हाइलाइट्स में से एक है अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क के 10-साल के अपडेट पर हस्ताक्षर, जो रक्षा और सुरक्षा में लगातार सहयोग को दर्शाता है। वीडियो में एक और अहम पल है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा।

फुटेज में प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक आवास पर वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चों की मेजबानी करते हुए दिख रहे हैं, जो लोगों से लोगों के बीच और नेतृत्व स्तर के संबंधों पर दिए गए जोर का संकेत देता है।

स्पेस और अर्थ साइंस पर जोर

वीडियो में स्पेस और अर्थ साइंस में सहयोग पर भी जोर दिया गया है। इसमें NISAR सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी शामिल है। इसमें ट्रंप प्रशासन के तहत सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए जाने का भी जिक्र है। दूतावास का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी जटिल रहे हैं।

इसमें पूरे साल सहयोग और टकराव दोनों देखने को मिले हैं। जहां रणनीतिक जुड़ाव जारी रहा है, वहीं व्यापार तनाव और तीखी बयानबाजी ने कई बार संबंधों में तनाव पैदा किया है। इसके बावजूद, दोनों पक्षों ने बार-बार इस साझेदारी के लंबे समय के महत्व पर जोर दिया है।

1 जनवरी 2026 से लागू होंगे बड़े नियम: LPG, UPI, ITR, क्रेडिट स्कोर और PAN-Aadhaar में बदलाव

संवाददाता | NEWS AGENCY

नई दिल्ली – 1 जनवरी 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक नियम बदलकर लागू हो जाएंगे, जो आम जनता के रोज़मर्रा के जीवन और जेब पर असर डालेंगे। आयकर विभाग के अनुसार अब रिवाइज्ड ITR (आयकर रिटर्न) फाइल नहीं किया जा सकेगा और यह विकल्प 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा; उसके बाद अपडेटेड ITR-U ही इस्तेमाल होगा। क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते अपडेट होगा, जिससे लोन पात्रता और ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली वास्तविक वित्तीय स्थिति अधिक तेज़ी से प्रतिबिंबित होगी। PAN-Aadhaar लिंकिंग की डेडलाइन समाप्त होने के बाद बिना लिंक किये PAN कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग और कर संबंधी सुविधाओं पर असर पड़ेगा। घरेलू और व्यावसायिक LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है, वहीं UPI और डिजिटल भुगतान पर नियम और सख्ती लागू होगी ताकि धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखा जा सके। इन बदलावों के साथ ही कई सरकारी योजनाओं और नियमों में अपडेटेड प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

नड्डा का कांग्रेस पर तीखा हमला: खरगे के आरोपों को बताया 'झूठ की खेती'

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर आरोप लगाया है कि वे लगातार झूठा प्रचार और भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि जनता ने 2025 में कांग्रेस को कई महत्वपूर्ण राज्यों में तेजी से पीछे कर दिया है। नड्डा ने ट्विटर (एक्स) पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब "झूठ फैलाने" के अलावा कुछ भी शेष नहीं है और पार्टी लगातार अपनी **हार के बावजूद आरोपों को जारी रखे हुए है।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव हारे हैं और दिल्ली तथा बिहार में पार्टी का सफाया हो गया है, फिर भी खरगे देश की राजनीतिक स्थिति पर भ्रामक बयान जारी रखे हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से खरगे द्वारा महामारी रोजगार योजना मनरेगा (MGNREGA) को लेकर लगाए गए आरोपों को असत्य बताया और कहा कि दरअसल सरकार ने इसे विस्तारित किया है, कार्यदिवस बढ़ाए हैं और भुगतान समय सुनिश्चित किया है।

नड्डा ने मतदाता अधिकारों, SIR और BLO जैसे चुनावी मामलों पर कांग्रेस के दावों को भी खारिज किया और सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस के पास वास्तविक शिकायतें होतीं तो चुनाव आयोग के समक्ष कितनी शिकायतें दायर कीं?

The Times of India

उन्होंने कहा कि खरगे की आलोचना न केवल सरकार की नीतियों पर है, बल्कि भारत की सेना, न्यायपालिका और आर्थिक प्रगति पर भी गलत जानकारी फैलाने जैसी बातों को लेकर है।

बीजेपी प्रमुख ने यह भी तंज कसा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊँचाई पर है, लेकिन कांग्रेस इसे मानने से इनकार कर रही है।

The Times of India

नड्डा ने कहा कि इन सब मुद्दों पर कांग्रेस की निरंतर आलोचना और आरोप लगाना राजनीतिक हताशा की निशानी है और उन्होंने खरगे से आत्मनिरीक्षण करने की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बयानबाजी महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती शब्दयुद्ध का प्रतिबिंब है, जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ कठोर आरोप लगा रहे हैं।

बांग्लादेश में मोहम्मद युनूस से क्यों नहीं हुई विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात? जानें क्या हैं मायने

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। जयशंकर का हवाई अड्डे पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने स्वागत किया। जयशंकर अंतिम संस्कार में भारत सरकार और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने पहुंचे जयशंकर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता और पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। हालांकि, जयशंकर की बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस से कोई मुलाकात नहीं हुई।

युनूस से मुलाकात नहीं होने को लेकर कयास

बांग्लादेश में होने के बावजूद मोहम्मद युनूस से मुलाकात नहीं होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर जयशंकर की यूनूस से मुलाकात क्यों नहीं हुई? क्या यह भारत सरकार का सोचा-समझा कदम है? यदि ऐसा है तो भारत आखिर इस रुख से क्या संदेश देना चाहता है। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई।

विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि ढाका में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के बीच कोई मीटिंग नहीं हुई। इस्लाम समर्थक यूनुस बांग्लादेश में हमले का शिकार हो रहे अल्पसंख्यक समुदायों को न्याय दिलाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपने इस रुख से परोक्ष रूप से एक संदेश देने का काम किया है। जयशंकर ने बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान से मुलाकात की। इससे ढाका को एकदम साफ और स्पष्ट संदेश मिल गया।

भारत का स्थिर और सतर्क रुख

कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि भारत का रुख ढाका में राजनीतिक बदलाव को लेकर अनिश्चितताओं और नए सिस्टम की वैधता और स्थिरता पर सवालों के बीच उसके सतर्क रुख का संकेत देता है। नई दिल्ली के लिए, संतुलित रवैया बनाए रखना जरूरी है। भारत के लिए बांग्लादेश के लोकतांत्रिक रोडमैप को सपोर्ट करना और साथ ही पड़ोस में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा करना प्राथमिकता में सबसे पहले हैं।

भारत का स्थिर और सतर्क रुख

कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि भारत का रुख ढाका में राजनीतिक बदलाव को लेकर अनिश्चितताओं और नए सिस्टम की वैधता और स्थिरता पर सवालों के बीच उसके सतर्क रुख का संकेत देता है। नई दिल्ली के लिए, संतुलित रवैया बनाए रखना जरूरी है। भारत के लिए बांग्लादेश के लोकतांत्रिक रोडमैप को सपोर्ट करना और साथ ही पड़ोस में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा करना प्राथमिकता में सबसे पहले हैं।

भारतीय सेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मार गिराए 237 ड्रोन

नई दिल्ली – रक्षा मंत्रालय ने साल 2025 के दौरान पाकिस्तान से सटे अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर कुल 791 ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी समाजी। इनमें जम्मू-कश्मीर में 9 और पंजाब तथा राजस्थान में 782 घटनाएँ शामिल हैं, जिससे सीमावर्ती सुरक्षा चुनौती बनी रही।

सालांत समीक्षा में बताया गया कि भारतीय सेनाओं ने 237 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 5 ड्रोन युद्ध सामग्री, 72 ड्रोन नशीले पदार्थ, और 161 बिना पेलोड वाले ड्रोन थे।

पश्चिमी मोर्चे पर स्पूफर और जैमर तकनीक के इस्तेमाल से ड्रोन खतरे का सामना प्रभावी ढंग से किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है और सीमा पर तैनाती मजबूत है। घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि ड्रोन आधारित घुसपैठ की चुनौतियाँ बढ़ी हैं, हालांकि सुरक्षा उपायों से उनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सका है।

लाहौर में लश्कर-ए-तैय्यबा की बैठक उजागर करती है पाकिस्तान का दोहरा आतंकवाद रवैया

नई दिल्ली / लाहौर — पाकिस्तान में आतंकवाद और उसकी कथित नीति पर गंभीर सवाल उठ गए हैं जब लश्कर-ए-तैय्यबा (LeT) और जुड़े आतंकियों की लाहौर में खुलेआम हुई बैठक का तीन-घंटे का लाइव वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आतंकवादी स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया, जो हाफिज सईद द्वारा समर्थित राजनीति समूह है।

वीडियो में LeT के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी को सुनाया गया है कि भारत "अगले 50 वर्षों तक पाकिस्तान को चुनौती नहीं देगा," और वह कश्मीर मुद्दे के समर्थन की बात दोहरा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में कुछ संगठनों को खुले मंच पर गतिविधि

करने की स्वीकृति है — यह उन दावों के विपरीत है जिनमें कहा जाता रहा है कि आतंकवादी तत्वों को देश की मिट्टी पर पनाह नहीं दी जाती।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी नीति पर गंभीर संदेह उठाता है, और यह कि यह राज्य आतंकवादियों को मंच प्रदान कर रहा है।

इससे दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थितियों में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है, खासकर सीमांत सुरक्षा मामलों को लेकर। यह घटना अंतरराष्ट्रीय समुदाय और रणनीतिक विशेषज्ञों को पाकिस्तान की आतंकवाद-विरोधी प्रतिबद्धताओं की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है।

पीएम मोदी ने 'प्रगति' 50वीं बैठक में सुधार और परिवर्तन पर जोर दिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की।

यह बैठक पिछले एक दशक में शासन की संस्कृति में आए गहरे परिवर्तन का प्रतीक है। प्रगति प्लेटफॉर्म ने अब तक 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को गति प्रदान की है और सहकारी संघवाद को मजबूत किया है।

बैठक में प्रधानमंत्री ने परियोजना जीवन चक्र के हर चरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में प्रगति मंच को और मजबूत करना होगा ताकि नागरिकों को तेज क्रियान्वयन, उच्च गुणवत्ता और मापने योग्य परिणाम मिलें। उन्होंने अगले चरण के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया - "सरलता के लिए सुधार, परिणाम देने के लिए प्रदर्शन, प्रभाव डालने के लिए रूपांतरण"।

सुधार का अर्थ प्रक्रियाओं को सरल बनाना, समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना और जीवन की सुगमता तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देना।

प्रदर्शन का मतलब समय, लागत और गुणवत्ता पर समान ध्यान देना।

रूपांतरण को नागरिकों की भावनाओं से मापा जाना चाहिए - समय पर सेवाएं, शिकायतों का त्वरित समाधान और जीवनयापन में सुधार।

बैठक में प्रमुख समीक्षा

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं: सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्रों की पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। ये परियोजनाएं पांच राज्यों में फैली हैं और इनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

पीएम श्री योजना: प्रधानमंत्री ने इसे समग्र और भविष्योन्मुखी स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बनाने पर बल दिया। बुनियादी ढांचे के बजाय परिणाम-उन्मुख क्रियान्वयन पर फोकस हो। सभी मुख्य सचिवों को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। पीएम श्री स्कूलों को अन्य राज्य स्कूलों के लिए बेंचमार्क बनाने और वरिष्ठ अधिकारियों को जमीनी दौरे करने का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ने प्रगति को गुजरात में मुख्यमंत्री रहते शुरू किए 'स्वागत' प्लेटफॉर्म का राष्ट्रीय विस्तार बताया। यह अलग-थलग कार्यप्रणाली को तोड़ता है और सभी हितधारकों को एक मंच पर लाता है। अब तक केंद्र के लगभग 500 सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों ने इसमें भाग लिया।

पीएम मोदी ने कहा कि जब निर्णय समय पर होते हैं, समन्वय प्रभावी होता है और जवाबदेही तय होती है, तो शासन की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। प्रगति विकसित भारत@2047 के लक्ष्य का शक्तिशाली उत्प्रेरक है।

उन्होंने राज्यों को सामाजिक क्षेत्र में मुख्य सचिव स्तर पर समान व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।यह बैठक भारत की तेज प्रगति के साथ प्रगति मंच की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।

महाराष्ट्र की राजनीति : चुनावी शोर में जनता के सवाल

संपादकीय... |

वर्ष 2025 का अंतिम दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कई मायनों में निर्णायक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। एक ओर आगामी महानगरपालिका और नगर परिषद चुनावों की आहट है, तो दूसरी ओर गठबंधनों में टूट-फूट, दल-बदल और आपसी आरोप-प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को अस्थिर बना दिया है। इस पूरे शोर-शराबे के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सत्ता और विपक्ष—दोनों ही—जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं?

महाराष्ट्र की राजनीति लंबे समय से गठबंधन धर्म के सहारे चलती रही है। वर्ष 2025 के अंत तक आते-आते यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दल चुनावी गणित में उलझकर नीति और प्रशासन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कहीं सीटों के बंटवारे पर खींचतान है, तो कहीं पुराने साथी एक-दूसरे पर अविश्वास जता रहे हैं। नतीजतन, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो रही है।

आज महाराष्ट्र के शहरों और कस्बों में जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, वे किसी से छिपी नहीं हैं। पानी की किल्लत, जलभराव, खराब सड़कें, महंगाई, बेरोजगारी और नागरिक सुविधाओं की बदहाली—ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा असर आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। लेकिन चुनावी भाषणों और राजनीतिक बयानबाज़ी में इन सवालों की जगह अक्सर व्यक्तिगत आरोप, इतिहास की बहस और सत्ता संघर्ष ले लेते हैं।

खासतौर पर शहरी निकायों की बात करें तो महानगरपालिकाएं विकास की धुरी मानी जाती हैं। यहां से लिए गए फैसले करोड़ों नागरिकों की रोज़मर्रा की जिंदगी तय करते हैं। इसके बावजूद, स्थानीय स्वशासन की आत्मा को कमजोर किया जाना चिंता का विषय है। चुनाव समय पर न होना, प्रशासकीय नियंत्रण का बढ़ना और राजनीतिक अस्थिरता—इन सबका खामियाजा अंततः जनता को भुगतना पड़ता है।

राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी तस्वीर अलग नहीं है। किसानों को फसल का वाजिब दाम, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षित माहौल—ये वादे हर चुनाव में दोहराए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर सीमित दिखाई देता है। वर्ष 2025 के अंत में खड़े होकर जनता यह सवाल पूछने को मजबूर है कि क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने की कवायद बनकर रह गया है?

राजनीतिक दलों के लिए यह आत्ममंथन का समय है। सत्ता में रहना लक्ष्य नहीं, बल्कि जनता की सेवा साधन होनी चाहिए—इस बुनियादी सिद्धांत को यदि भुला दिया गया, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि यहां की राजनीति विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही का उदाहरण पेश करे।

मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी इस दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल पूछना, तथ्य सामने लाना और जनहित को प्राथमिकता देना—यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अंधभक्ति या अंधविरोध—दोनों ही समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूरत है संतुलित सोच और जिम्मेदार नागरिकता की।

नए वर्ष 2026 की दहलीज पर खड़ा महाराष्ट्र एक बार फिर चुनावी दौर में प्रवेश करने जा रहा है। यह मौका है कि राजनीति जनता के मुद्दों की ओर लौटे, और मतदाता भी जाति, धर्म या भावनात्मक नारों से ऊपर उठकर काम, ईमानदारी और दूरदर्शिता के आधार पर फैसला करे।

अंततः लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि सत्ता का केंद्र जनता बने—न कि सत्ता की भूख। यदि महाराष्ट्र की राजनीति इस सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़े, तो आने वाला वर्ष न केवल राजनीतिक स्थिरता, बल्कि सामाजिक विश्वास और विकास का भी वर्ष बन सकता है।

नूर खान से मुरीदके तक... भारत ने जिन 11 पाकिस्तानी एयरबेसों पर किए हमले, जानें कैसी है उनकी हालत

मुंबई | इस्लामाबाद: भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान को यह अंदेशा नहीं था कि भारत का प्रहार इतना भयंकर होगा। भारत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तान के लगभग 11 प्रमुख एयरबेसों पर हमले किए थे। इन हमलों के कारण पाकिस्तान एयरबेस लंबे समय तक ऑपरेशनल नहीं हो सके। आज भारत को पाकिस्तानी एयरबेसों पर हमला किए सात महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस्लामाबाद आज भी उस नुकसान की भरपाई करने में जुटा है। ऐसे में इंडिया टुडे ने बताया है कि भारत के हमले से बर्बाद हुई पाकिस्तानी एयरबेसों का हाल कैसा है।

1) नूर खान एयरबेस
इस एयरबेस को पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत के हमले में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान मई 2025 से ही नूर खान एयरबेस की मरम्मत कर रहा है। नवंबर में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेमियन साइमन ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया था कि पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर एक नई फैसिलिटी का निर्माण कर रहा है। एक चीनी सैटेलाइट फर्म मिजाविजन की तस्वीरों में भी नूर खान एयरबेस पर नई इमारतें बनाए जाने की पुष्टि हुई है।

2) भोलारी एयरबेस
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के हमले से पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस लगभग तबाह हो गया था। इस हमले में भोलारी एयरबेस का हैंगर नष्ट हुआ था। इस हैंगर को अब तिरपाल से ढक दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि शायद तिरपाल के नीचे मरम्मत का काम चल रहा है। इस हमले में पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे। 3) मुरीदके एयरबेस
मुरीदके एयरबेस भारतीय सीमा के करीब स्थित है। पाकिस्तान ने यहां पर जेएफ-17, एफ-16 और कई ड्रोन तैनात कर रखे हैं। हालांकि, भारत के हमले में मुरीदके एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। फॉरवर्ड-ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नष्ट होने के बाद यह एयरबेस ऑपरेशनल परेशानियों का सामना कर रहा है। डेमियल साइमन की सैटेलाइट तस्वीर में मुरीदके एयरबेस की कमांड और कंट्रोल बिल्डिंग को एक विशाल लाल तिरपाल से ढका हुआ दिखाया गया है। इससे संकेत मिलता है कि यहां मरम्मत का काम जारी है।

4) मुशफ एयरबेस (सरगोधा)
पाकिस्तानी वायुसेना के मुशफ एयरबेस को सरगोधा एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुशफ एयरबेस को निशाना बनाया था। इससे इसका कमांड-एंड-कंट्रोल बिल्डिंग समेत कई महत्वपूर्ण इमारतें नष्ट हो गई थीं। इस कारण मुशफ एयरबेस से सीमित संख्या में में उड़ानें ऑपरेट की जा रही हैं। भारत के हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में मुशफ एयरबेस के रनवे पर दो बड़े गड्ढे दिखे थे, जिनका दायरा 15 फीट से ज्यादा का था। हालांकि, पाकिस्तान ने अब इस एयरबेस के रनवे की मरम्मत कर दी है।

WORLD NEWS नए साल का आगाज

2026 का पहला स्वागत: न्यूजीलैंड बना दूसरा देश, जानें कौन पहला था

● NEWS AGENCY

वेलिंगटन: न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया है। यह साल 2026 का स्वागत करने वाला दूसरा देश बन गया है। इस मौके पर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी की गई। इसने शहर के आइकॉनिक स्काई टॉवर के ऊपर आसमान को रोशन कर दिया। इस मौके का गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशों से आए टूरिस्ट शामिल हैं। हालांकि, न्यूजीलैंड नए साल का स्वागत करने वाला दूसरा देश है। इससे पहले भी एक देश नए साल का स्वागत कर चुका है।

न्यूजीलैंड में कहां मना जश्न
न्यूजीलैंड में नए साल का मुख्य समारोह ऑकलैंड के स्काई टॉवर के पास मनाया गया। इस दौरान यहां नए साल के स्वागत के लिए काउंटडाउन भी किया गया, जिसे हजारों की भीड़ ने चीयर किया। न्यूजीलैंड में, चैथम द्वीप समूह सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। पांच मिनट के इस शो में न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत, 240-मीटर (787-फुट) ऊंचे स्काई टॉवर की अलग-अलग मंजिलों से 3,500 आतिशबाजी की गई।
नए साल का जश्न मनाने वाला पहला देश

प्रशांत महासागर में स्थित देश किरिबाती का किरीतिमाटी द्वीप, दुनिया में नए साल का स्वागत करने वाला पहला स्थान है। यह द्वीप, जो UTC+14 टाइम ज़ोन में स्थित है, क्रिसमस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किरिबाती की कुल भूमि क्षेत्र 811 वर्ग किमी (313 वर्ग मील) है। किरीबाती में प्रवासी भारतीयों की भी एक महत्वपूर्ण संख्या है।
किरिबाती: दोपहर 3:30 बजे IST (31 दिसंबर),
न्यूजीलैंड: शाम 4:30 बजे IST (31 दिसंबर),

किस देश में कब शुरू होगा नया साल

ऑस्ट्रेलिया (पूर्वी तट): शाम 6:30 बजे IST (31 दिसंबर),
जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया: रात 8:30 बजे IST (31 दिसंबर),
चीन, हांगकांग और ताइवान: रात 9:30 बजे IST (31 दिसंबर),
थाईलैंड: रात 10:30 बजे IST (31 दिसंबर),
भारत और श्रीलंका: रात 12:00 बजे IST (आधी रात),
रूस (मॉस्को): सुबह 2:30 बजे IST (1 जनवरी),
यूक्रेन: सुबह 3:30 बजे IST (1 जनवरी),
जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और स्विट्जरलैंड: सुबह 4:30 बजे IST (1 जनवरी),
यूके, पुर्तगाल और घाना: सुबह 5:30 बजे IST (1 जनवरी),
ब्राजील और अर्जेंटीना: सुबह 8:30 बजे IST (1 जनवरी),
अमेरिका (पूर्वी तट): सुबह 10:30 बजे IST (1 जनवरी),

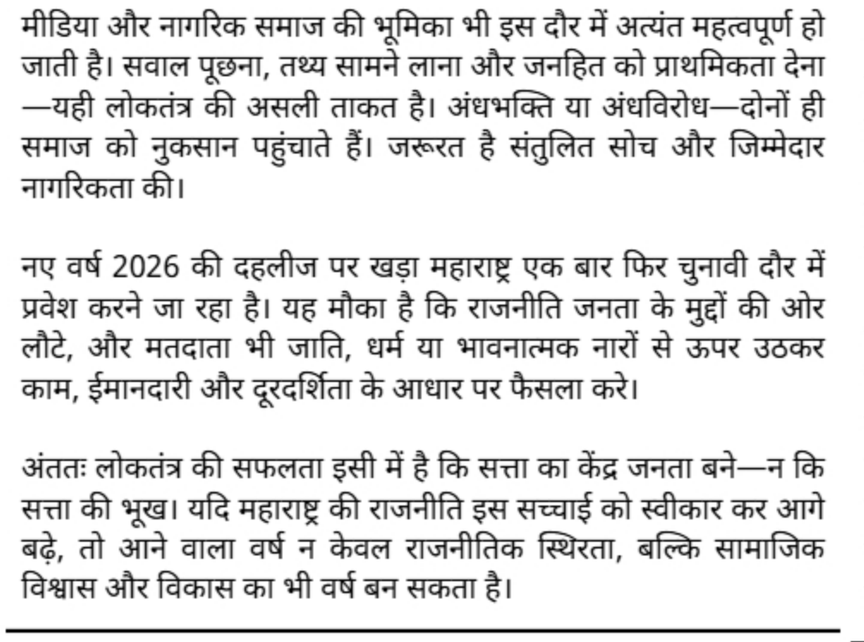

भारत 50 साल तक हमले की जुर्रत नहीं करेगा... ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर बोला हाफिज सईद, खुलासा

इस्लामाबाद: जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने एक बार फिर से पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने के ऐलान पर हाफिज सईद ने कहा कि भारत केवल खाली धमकी दे रहा है। भारत से डरने की जरूरत नहीं है। भारत अगले 50 साल तक हमले का अब साहस नहीं कर पाएगा। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए- तैयबा के डेप्युटी चीफ सैफुल्ला कसूरी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सैफुल्ला कसूरी ने इस वीडियो में भारत के खिलाफ जहर उगला और हाफिज सईद के हवाले से यह दावा किया है।

सैफुल्ला कसूरी ने दावा किया कि वह एक डेढ़ महीने पर एक मजलिस में था जिसमें हाफिज सईद भी मौजूद था। इस बैठक के दौरान एक पाकिस्तानी ने हाफिज सईद से सवाल किया कि भारत लगतार पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे रहा है और इस खतरे को कैसे देखा जाना चाहिए। सैफुल्ला कसूरी ने बताया कि हाफिज सईद ने इसका जवाब दिया और कहा, 'हमें भारत की खाली धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 6 महीने पहले अल्लाह ने ऐसा गहरा जख्म दिया है कि वह अगले 50 साल तक दोबारा हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा।'

बता दें कि पाकिस्तान का दावा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है लेकिन सैफुल्ला कसूरी के इस खुलासे से साफ है कि लश्कर सरगना खुलेआम जलसे कर रहा है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित कर रखा है। हाल ही में लश्कर के कमांडरों ने पाकिस्तान में बैठक की है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति बनाई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक बार फिर से कश्मीर पर जेहादी हिंसा को भड़काना चाहते हैं और इसमें लश्कर उनकी पूरी मदद कर सकता है।

सैफुल्ला कसूरी ने कहा, 'भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी गलती की है। कसूरी ने कहा कि हमारे अपने भी सुन लें और बाहरी भी सुन लें। दोस्त भी सुन लें और दुश्मन भी सुन लें। जिन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, वे भी सुन लें। जो लोग हमारे चेहरों को आतंकी बता रहे हैं, वे भी सुन लें। पूरी दुनिया सुन ले। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मैं हजारों लोगों के सामने ऐलान करता हूं कि कश्मीर के लोगों की मदद से हम पीछे नहीं हटेंगे।' कसूरी ने दावा किया, 'भारत ने कश्मीर, अमृतसर, होशियापुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनावदार, हैदराबाद, दक्कन, बंगाल पर कब्जा किया है जहां पर मुस्लिम बहुमत में हैं। ये पाकिस्तान का इलाका है। इसे पाकिस्तान से लिया गया है। हम इसे संयुक्त राष्ट्र ले जाएंगे।'

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Thursday 1st January 2026 वर्ष - 9 , अंक 246 , पृष्ठ 03

महाराष्ट्र सरकार ने सीनियर आईपीएस सदानंद दाते को राज्य का नया DGP नियुक्त किया

मुंबई – महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को **राज्य का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) नियुक्त किया है। दाते 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और वे 3 जनवरी 2026 से मौजूदा DGP रश्मि शुक्ला की जगह राज्य पुलिस बल की कमान संभालेंगे। दाते की नियुक्ति गृह विभाग के आदेश के तहत की गई है और उन्हें दो साल के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार डीजीपी पद पर सेवा की स्थिरता सुनिश्चित करेगी।

सदानंद दाते राष्ट्रीय स्तर पर 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां उन्होंने आतंकियों का मुकाबला किया और उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलब्लिटी से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनके पास राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक के रूप में सेवा का अनुभव है और उन्होंने विभिन्न उच्चस्तरीय सुरक्षा और पुलिस संचालन पदों पर कार्य किया है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि दाते का नेतृत्व राज्य में कानून-व्यवस्था की मजबूती और सुरक्षा प्रबंधन को और प्रभावी बनाएगा।

MAHARASHTRA| Maharashtra Municipal Election 2026

Maharashtra Municipal Election: महानगरपालिका चुनाव में 2896 सीटों पर 33606 नामांकन, हर सीट पर औसतन 11 प्रत्याशी

मुंबई | मुंबई: महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन प्राप्त होने की अंतिम रिपोर्ट जारी की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 29 महानगर पालिकाओं की कुल 2,869 सीटों के लिए कुल 33,606 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। राज्यभर की 29 महानगरपालिकाओं में औसतन हर सीट पर 11 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जो इस चुनाव के रोमांचक होने का संकेत दे रहे हैं। नामांकन के आंकड़ों को देखें तो मुंबई और पुणे में सबसे कड़ी टक्कर होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई थी और 30 दिसंबर को समाप्त हुई। अधिकारियों के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हो गई,

जबकि उम्मीदवार दो जनवरी को अपराह्न तीन बजे तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।पुणे महानगरपालिका में रिकॉर्ड 3179 नामांकन

राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पुणे महानगरपालिका की कुल 165 सीटों के लिए रिकॉर्ड 3179 नामांकन प्राप्त हुए तो मुंबई महानगरपालिका की 227 सीटों के लिए कुल 2,516 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। आंकड़ों के मुताबिक पनवेल महानगरपालिका में सबसे कम प्रतिस्पर्धा दिख रही है, जहां 78 सीटों के लिए केवल 391 नामांकन प्राप्त हुए हैं । इसके बाद इचलकरंजी का नंबर आता है, जहां 65 सीटों के लिए 456 दावेदार सामने आए हैं।

नवी मुंबई में 111 सीटों के लिए 956 नामांकन

नवी मुंबई में 111 सीटों के लिए 956 नामांकन, वसई-विरार मनपा में 115 सीटों के लिए 956 नामांकन, कल्याण-डोंबिवली मनपा की कुल 122 सीटों के लिए 860 नामांकन, ठाणे मनपा की 131 सीटों के लिए 1128 नामांकन, उल्हासनगर मनपा की 78 सीटों के लिए 706 नामांकन, नाशिक मनपा की 122 सीटों के लिए 2356 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसी तरह पिंपरी चिंचवड में 1993 नामांकन, भिवंडी-निजामपुर में 1033, पनवेल में 391, मीरा-भायंदर में 632 नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

शिवसेना (UBT) में टिकट विवाद: अंबादास दातें पर महिला टिकट काटने और BJP मदद के आरोप

छत्रपती संभाजीनगर / मुंबई: आगामी नगर पालिका चुनाव 2026 के बीच शिवसेना (UBT) में भीतरघात और टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर विवाद उभर चुका है। वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे ने पार्टी के पूर्व विरोधी पक्षनेता अंबादास दातें पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भाजपा (BJP) की मदद के लिए संभावित विजयी महिला उम्मीदवारों के टिकट काट दिए। खैरे के मुताबिक इस कदम से शिवसेना की जीत की संभावनाएँ कमजोर हुई और संगठनात्मक एकता को चोट पहुँची है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म होता दिख रहा है।

खैरे का कहना है कि जिन महिलाओं को टिकट मिलना अपेक्षित था, उन्हें नज़रअंदाज़ किए जाने से कई महिला कार्यकर्ता रो पड़े और भूख हड़ताल तक पर बैठ गए। कुछ महिलाओं ने टिकट कटने पर पार्टी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल भी शुरू की, जिससे स्थानीय राजनीति में और तनाव पैदा हुआ। इस असंतोष के बीच समर्थक कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच सख्त शब्दों का आदान-प्रदान जारी रहा है।

वहीं खैरे ने आरोप लगाया कि दातें ने पूर्व कांग्रेस महापौर रशीद मामू को भी शिवसेना में शामिल कर गरम पानी वार्ड से उम्मीदवार बनाया, जबकि खैरे इसके खिलाफ थे। खैरे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ प्रचार नहीं करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उन्हें यह कदम प्रतिष्ठा पर चोट लगता है।

इस विवाद ने शिवसेना (UBT) के भीतर भितरघात की तस्वीर को और उजागर किया है, जहाँ टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता खैरे ने कहा है कि टिकट वितरण अधिक पारदर्शी और समावेशी होना चाहिए, ताकि महिला कार्यकर्ताओं सहित अन्य योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सकें।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह विवाद छत्रपती संभाजीनगर महापालिका चुनाव में शिवसेना की स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर जब बीजेपी और अन्य दल भी चुनावी तैयारियाँ तेज़ कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने नाशिक-सोलापुर-अक्कलकोट 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी

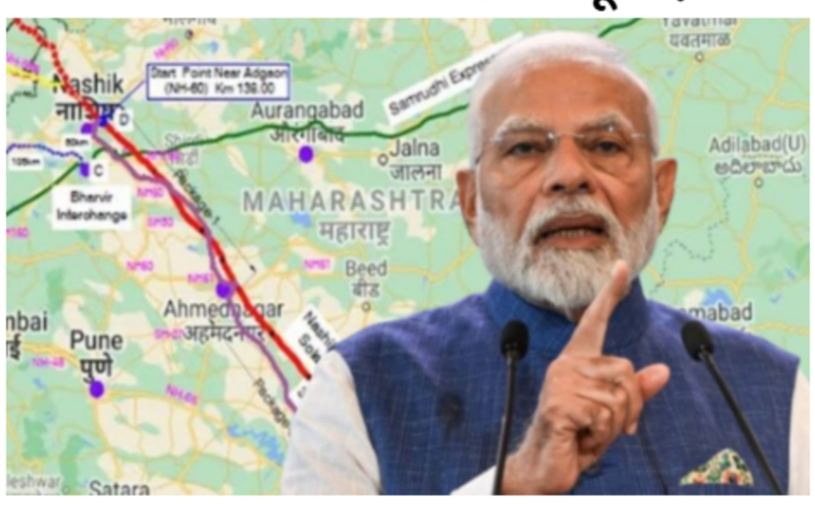

संवाददाता | NEWS AGENCY

नई दिल्ली / महाराष्ट्र - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 374 किलोमीटर लंबे नाशिक-सोलापुर-अक्कलकोट छह-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका कुल अनुमानित खर्च ₹19,142 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट बीओटी (टोल) मोड में विकसित किया जाएगा और उत्तर तथा दक्षिण महाराष्ट्र को मजबूत पश्चिम-पूर्व कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे माल और लोगों का आवागमन तेज़ और सुरक्षित होगा।

इस मंजूरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने मराठी में ट्वीट किया, जिसमें कहा कि यह 'गति शक्ति' योजना से जुड़ा परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट है, जो यात्रा के समय को कम करेगा, लॉजिस्टिक्स को सशक्त करेगा और नये रोजगार सृजन में मदद करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह मार्ग नाशिक से सोलापुर व अक्कलकोट के बीच यात्रा दूरी को लगभग 201 किमी तक घटाकर यात्रा समय को लगभग 17 घंटे तक कम करेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव: गठबंधन सियासत तेज, महायुति और महाविकास आघाड़ी में रणनीति बदली

मुंबई: महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए आगामी चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं, जहाँ बड़े दलों और गठबंधनों ने अपनी चुनावी रणनीतियाँ अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ये चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं और मतगणना 16 जनवरी को निर्धारित है, जिससे पहले ही सभी पार्टियों ने नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है।

सबसे बड़ी सियासी तस्वीर के रूप में महायुति (बीजेपी-शिंदे शिवसेना) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित कई निगमों में सीट शेयरिंग तय कर ली है, जिसमें बीजेपी 137 और शिंदे-नेता शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनसीपी (अजित पवार) गठबंधन से बाहर है और स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतार रही है।

वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी में भी गठबंधन समीकरण बदले दिख रहे हैं। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने मनसे और एनसीपी (Sharad Pawar) जैसे दलों के साथ कुछ स्थानीय निकायों में तालमेल बनाया है, तथा कांग्रेस भी कुछ नगर निगमों में VBA और क्षेत्रीय घटकों के साथ गठबंधन की दिशा में सक्रिय है, जबकि कुछ स्थानों पर पार्टियाँ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही हैं।

राजनीति विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव महाविकास आघाड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि महायुति गठबंधन ने कई महानगरों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और शुरुआती चरण में भाजपा के कई उम्मीदवार बिना मुकाबले जीत भी चुके हैं, जिससे सत्तारुढ़ गठबंधन को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है।

मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे और नासिक जैसे प्रमुख नगर निगमों में गठबंधन और सीट-बंटवारे की आख़िरी रूपरेखा तैयार होने के साथ ही स्थानीय मुद्दों और जनहित के बारे में चुनावी प्रचार तेज हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती और गठबंधन की स्थिति अंतिम परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगी।

परभणी महापालिका चुनाव 2026: शिंदे सेना ने सुरेश वरपूडकर पर गठबंधन तोड़ने का आरोप

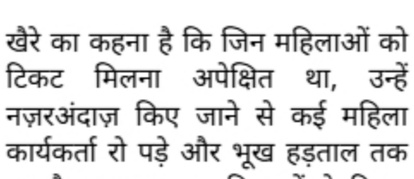

परभणी (महाराष्ट्र): परभणी महानगरपालिका चुनाव 2026 में शिंदे सेना ने भाजपा नेता सुरेश वरपूड़कर पर महायुति (गठबंधन) तोड़ने का आरोप लगाया है। शिंदे सेना के जिल्हाप्रमुख आनंद भरोसे ने कहा कि भाजपा ने गठबंधन के तहत हिंदुबहुल क्षेत्रों में 33 में से केवल 12 सीटें देने का प्रस्ताव दिया, जबकि पहले अधिक देने का वादा किया गया था। इसके बाद वरपूड़कर ने अपने घर-गृहस्थी से जुड़े कारणों से गठबंधन बिगाड़ दिया, जिससे युति कमजोर हुई। भरोसे ने यह भी कहा कि भाजपा ने दिए गए शब्द का पालन नहीं किया और यह कदम गठबंधन के हितों को नुकसान पहुँचाने वाला है।

वरपूड़कर ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि टिकट वितरण और सामाजिक समीकरणों के आधार पर निर्णय लिया गया और उन्होंने गठबंधन को बचाने का प्रयास जारी रखने का दावा किया।

बीएमसी चुनाव में 12 महायुति उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, आठवले-फडणवीस बैठक के बाद अहम निर्णय

मुंबई — आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 से पहले महायुति (भाजपा-शिंदे शिवसेना) गठबंधन में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उभर आया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री और आरपीआई (आठवले) प्रमुख रामदास आठवले ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और महायुति द्वारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई-ए) को BMC चुनाव के लिए सीट आवंटन में न शामिल किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई। बैठक के बाद महायुति में सहमति बन गई कि भाजपा और शिंदे शिवसेना अपने-अपने कोटे से कुल लगभग 12 सीटें आरपीआई को देगी। इन सीटों पर महायुति के वर्तमान उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और आरपीआई उम्मीदवारों को समर्थन देंगे।

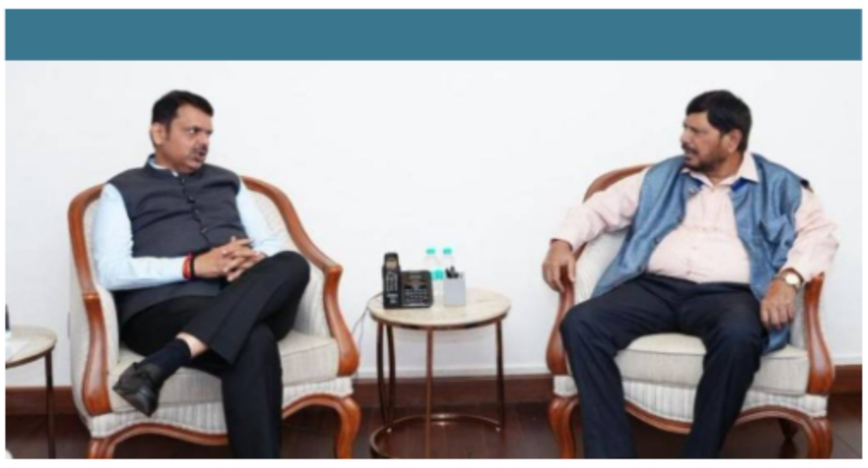

आरपीआई ने मुख्यमंत्री फडणवीस को 17 चुनावी सीटों की सूची सौंपी थी, जिनमें से कम से कम 12 सीटें भाजपा-शिंदे शिवसेना ने आरपीआई को देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा शेष 197 वार्डों में आरपीआई महायुति का समर्थन करते हुए प्रचार करेगी।

यह कदम महायुति गठबंधन और आरपीआई के बीच मतभेदों के बीच आया है, जहाँ आरपीआई ने शुरुआत में नाराजगी जताई थी कि उन्हें महत्त्वपूर्ण वार्डों में मौका नहीं मिला। इस समझौते को महापालिका चुनाव में गठबंधन को मजबूत बनाने और आरपीआई की नाराजगी दूर करने की कोशिश माना जा रहा है।

पुणे बम धमाका मामला: आरोपी बंटी जहागीरदार की श्रीरामपुर में गोली मारकर हत्या

अहिल्यानगर (महाराष्ट्र): 2012 के पुणे सिलसिलेवार बम धमाकों के एक प्रमुख आरोपी अस्लम शब्बीर उर्फ बंटी जहागीरदार को बुधवार दोपहर श्रीरामपुर शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास बोरावके कॉलेज रोड पर हुई, जब जहागीरदार एक श्मशान घाट से लौट रहे थे और उसी समय दो बाइक सवारों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जहागीरदार को छह गोलियाँ लगीं और गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस फायरिंग के पीछे का स्पष्ट मकसद अभी तक पुलिस जांच में सामने नहीं आया है।

पुलिस महानिदेशक सोमनाथ घरगे ने बताया कि हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना के बाद श्रीरामपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वरिष्ठ अधिकारी फॉरेन्सिक टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में भय और चिंता की स्थिति बनी हुई है।

बंटी जहागीरदार पर केवल बम धमाका मामला ही नहीं था, बल्कि हत्या, आपराधिक धमकी और खंडणी जैसे कई गंभीर मामलों में भी उनके खिलाफ 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जो उन्हें स्थानीय पुलिस और एटीएस दोनों की निगरानी में रखे हुए थे। वह 2012 के जंगली महाराज रोड धमाकों के मामले में महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और 2023 से जमानत पर बाहर थे। पुलिस अब हमलावरों की पहचान कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह हमला पुराने रंजिश या आपराधिक विवाद से जुड़ा है।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Thursday 1st January 2026 वर्ष - 9 , अंक 246 , पृष्ठ 04

नांदेड में सांसद श्रीकांत शिंदे की विश्वासी मिनल पाटील की उम्मीदवारी काटे जाने को लेकर विधायक कल्याणकर पर आरोप

नांदेड महानगरपालिका चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज़ हो गई है। वरिष्ट नेता *श्रीकांत शिंदे* के समर्थन से चल रही मिनल पाटील की उम्मीदवारी को अंतिम समय पर काटे जाने का आरोप चुनावी मैदान में उभरा है। स्थानीय सियासी सूत्रों के मुताबिक, श्रीकांत शिंदे की सलाह पर मिनल पाटील ने प्रभाग *नंबर 3* से उम्मीदवार के तौर पर काम शुरू किया था और प्रचार किया।

हालांकि आज अर्ज भरने के अंतिम दिन पार्टी नेतृत्व की तरफ से उनके नाम पर *एबी फॉर्म* नहीं दिया गया और उनकी जगह *श्याम कोकाटे* को उमेदवारी दी गई। इससे नाराज़ पाटील समर्थकों ने सीधे *विधायक बालाजी कल्याणकर* पर आरोप लगाए कि उन्होंने मिनल पाटील की उम्मीदवारी काटी और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आगे बढ़ाया। समर्थकों का कहना है कि यह फैसला स्थानीय स्तर पर विरोध और मतदाताओं की अपेक्षाओं के खिलाफ है।

मिनल पाटील के पक्षधर अब अपक्ष (इंडिपेंडेंट) उम्मीदवार के तौर पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नांदेड में सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है और इस घटना से चुनावी रणनीतियों पर सवाल उठने लगे हैं।

नांदेड महापालिका चुनाव 2025: भाजपा ने घराणेशाही का आरोप झेलते हुए पती-पत्नी को टिकट दिया

नांदेड : 2025 की नांदेड महापालिका चुनावी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बार फिर *घराणेशाही (डायनेस्टिक पॉलिटिक्स)* को लेकर विवादित फैसला किया है। पिछले लोहा नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को टिकट दिया था, जिन सभी को मतदाताओं ने करारी हार दी थी। बावजूद इसके, पार्टी ने इस बार नांदेड महापालिका के लिए एक ही परिवार के *पती-पत्नी दोनों को टिकट जारी किया है।*

भाजपा ने किशोर स्वामी और उनकी पत्नी शैलेजा स्वामी को महापालिका चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे और 2017 के चुनाव में विजय भी रहे चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें नए राजनीतिक मंच पर उतारा गया है।

इसके साथ ही पार्टी ने *पूर्व महापौर बलवंतसिंह गाडीवाले को भी प्रभाग क्रमांक 9 से टिकट दिया है और उनके पुत्र वीरेंद्रसिंह गाडीवाले को प्रभाग 10 से उम्मीदवार घोषित किया है।*

राजनीतिक पर्यवेक्षकों और विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा हमेशा से घराणेशाही के खिलाफ रही है, लेकिन स्थानीय चुनावों में यही रणनीति अपनाना विरोधाभासी है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे फैसले आम पार्टी कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं को पीछे छोड़ते हैं, जबकि पार्टी नेतृत्व अपने विश्वसनीय परिवारों को प्राथमिकता देता है।

स्थानीय कार्यकर्ता भी नाराज़गी जता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं रखी गई। वे मानते हैं कि भाजपा ने स्थानीय स्तर पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मियों को मौका नहीं देकर पार्टी की मूल भावना के विपरीत निर्णय लिया है।

भाजपा के इस फैसले से न केवल पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा है, बल्कि मतदाताओं के बीच भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह घराणेशाही रणनीति पार्टी को राजनीतिक लाभ दे पाएगी या इससे उसे नुकसान होगा, यह आगामी चुनाव परिणामों से स्पष्ट होगा।

नांदेड महापालिका चुनाव: बीजेपी ने मटका ऑपरेटर की पत्नी को टिकट देने को लेकर पूर्व पार्षद का बड़ा आरोप

नांदेड, महाराष्ट्र — आगामी *महापालिका चुनाव* से पहले बीजेपी पर टिकट वितरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रभाग क्रमांक *9* से भाजपा ने एक *मटका (गैंबलिंग) ऑपरेटर की पत्नी* को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसे लेकर *माजी नगरसेवक व्यंकटेश जिंदम* ने पार्टी और स्थानीय नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

जिंदम का दावा है कि इस प्रभाग में लंबे समय से सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज़ कर *बेग्राह (बाहरी)* व्यक्ति को टिकट देकर पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि यह टिकट *पैसे और दबाव के आधार पर* दिया गया है, न कि जनता के हित और पार्टी की नीतियों के अनुरूप। उनके अनुसार, भाजपा ने जिस मटका ऑपरेटर की पत्नी को टिकट दिया है, उसका पार्टी में योगदान सीमित है और वह हाल ही में पार्टी में शामिल हुई है।

जिंदम ने यह भी आरोप लगाया कि टिकट वितरण में *बीजेपी के स्थानीय नेता किशोर स्वामी के हस्तक्षेप* ने पारंपरिक कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि प्रभाग के कई पुराने समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी असहमति जताई है।

भाजपा की तरफ से इस आरोप पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी यह बताती आई है कि उसने उम्मीदवारों को स्थानीय जनहित और चुनावी रणनीति के आधार पर चुना है। चुनावी हलचल तेज़ होने के साथ ही यह विवाद प्रभाग के मतदाताओं के मन में असंतोष और उठते सवालों को और हवा दे रहा है।

चुनाव आयोग और राजनीतिक विश्लेषक भी टिकट वितरण और पार्टी निर्णयों के प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इनसे महापालिका चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है।

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव 2026: गठबंधन टूटा, भाजपा-शिवसेना-कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव *2026* की रौनक तेज़ हो गई है और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। *भाजपा और शिवसेना* के बीच महायुति गठबंधन बनाने की कोशिशें आख़िरकार सफल नहीं हो सकीं, जिससे दोनों दलों ने अलग-अलग उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसी बीच कांग्रेस ने *वंचित बहुजन आघाडी (VBA)* के साथ हाथ मिलाने का फ़ैसला किया है, ताकि मतों का विभाजन रोका जा सके और संयुक्त ताकत के रूप में चुनाव में उतरा जा सके।

भाजपा-शिवसेना युती के टूटने के बाद *भाजपा के महानगर अध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर* ने अपने पक्ष के उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने नांदेड उत्तर भाग और दक्षिण भाग समेत कई प्रभागों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं शिवसेना ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें पार्टी के स्थानीय और अनुभवी चेहरों को आमंत्रित किया गया है।

कांग्रेस की रणनीति में इस बार खास बदलाव देखा जा रहा है। पार्टी ने *61 सीटों पर खुद उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय* लिया है और *20 सीटें VBA* को देने का फ़ैसला किया है। इससे कांग्रेस-VBA के बीच गठजोड़ स्पष्ट हुआ है, जो महापालिका चुनाव में एक नई भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का एक गुट भी किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी में है।

भाजपा-शिवसेना के बीच युती टूटने का कारण उम्मीदवारों के सीट-वाटप और स्थानीय नेताओं के बीच मंथन बताया जा रहा है। शिवसेना के कुछ विधायक और कार्यकर्ता युति के पक्ष में थे, जबकि अन्य का रुख़ अलग था, जिससे अंतर पैदा हुआ और गठबंधन पटल से उतर गया।

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका में कुल *81 नगरसेवक* के लिए चुनाव होना है और इससे पहले उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। विभिन्न दलों के प्रचार और मतदाता संपर्क प्रयास अब तेज़ हो गए हैं, और आने वाले सप्ताह में मतदाताओं के बीच प्रचार की गति और बढ़ने की संभावना है।

नांदेड: छेड़छाड़ के मामले में जमानत पर छुटे आरोपी ने पीड़िता के पति को पेट्रोल छिड़ककर जलाया

संवाददाता

नांदेड जिले के नायगाव तालुका के बेंद्री गाँव में 29 दिसंबर सुबह साढ़े पांच बजे एक भयावह घटना सामने आई, जहाँ छेड़छाड़ का मामला दर्ज होने के बाद जमानत पर बाहर आये मुख्य आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने पीड़िता के पति को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया। पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया और उसे पहले नायगाव अस्पताल में भर्ती किया गया, बाद में हालत गंभीर होने पर नांदेड रेफर किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी संतोष बेंद्रीकर, उसके पिता माधव विश्वनाथ बेंद्रीकर और भाई शिवकुमार माधव बेंद्रीकर को गिरफ्तार किया।

घटना से पहले 22 दिसंबर को संतोष ने अपने पड़ोस में रहने वाली विवाहित महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके खिलाफ पीड़िता ने नायगाव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और मामला दर्ज हुआ था। आरोपी संतोष फरार था, लेकिन 28 दिसंबर को पुलिस ने उसे नरसी से पकड़ा और न्यायालय से उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। अंततः विवाद इतनी खूनी रवानी में बदल गया कि उन्होंने पीड़िता के पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने गाँव में बढ़ते तनाव को देखते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

नांदेड लोहा: शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, तीन दुकानों में 40 लाख रुपए से अधिक का नुकसान

नांदेड जिले के *लोहा शहर* में सोमवार रात लगभग *10 बजे* भयंकर आग लगने की घटना में तीन दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। यह अग्निकांड मुख्य सड़क पर स्थित *राधाई हार्डवेयर एंड पेंट हाउस, **वैष्णवी बॉडी बिल्डर्स* और *शिवकाशी वेल्डिंग वर्कशॉप* नामक दुकानों में फैला। प्रारंभिक जांच के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण *शॉर्ट सर्किट* बताया जा रहा है, जिससे इन दुकानों का लगभग *40 लाख रुपये* का माल व दुकान की सामग्री नष्ट हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के प्रयासों के दौरान आसपास के व्यापारियों और निवासियों में अफरा-तफरी देखने को मिली, लेकिन धन और माल का व्यापक नुकसान होने के बावजूद कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ।

घटना के अगले दिन *आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर* और अन्य स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा प्रभावित दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने प्रशासन को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने और पंचनामा तैयार करने के निर्देश दिए। महावितरण के अधिकारियों तथा नगर निगम प्रतिनिधियों ने भी वहां पहुंचकर अग्निकांड के बाद स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने आग लगने की सही वजह का पता लगाने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जांच जारी रखी है।

छत्रपति संभाजीनगर: बीजेपी में टिकट विवाद से आंतरिक संकट, नाराज कार्यकर्ताओं ने नेताओं को घेरकर किया प्रदर्शन

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): आगामी महानगरपालिका चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के भीतर गंभीर आंतरिक संकट उभर आया है, जहाँ टिकट वितरण को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया। टिकट सूची जारी होने के बाद कई निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी भड़क उठी, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष का माहौल बन गया है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री अतुल सावे और सांसद डॉ. भागवत कराड के वाहनों को घेरकर घोषणाबाजी की और नेताओं को शिव्यांकित किया, जिससे पार्टी के भीतर कठोर शब्दों का आदान-प्रदान हुआ।

कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला और कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ नेताओं को सर्वे के बहाने/पसंदीदा लोगों को प्राथमिकता दी गई जबकि स्थानीय, अनुभवी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज़ किया गया। इससे गुस्से में कुछ कार्यकर्ताओं ने आत्मदहन की कोशिश जैसी ड्रामाई कार्रवाई तक की, हालांकि पुलिस और वरिष्ठ नेताओं ने समय रहते स्थिति को काबू में किया।

इस विवाद के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने भी उपोषण शुरू किया और कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल की, जिससे असंतोष और गहरा गया। कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पारदर्शी या निष्पक्ष नहीं थी और पार्टी नेतृत्व को इसका तुरंत समाधान निकालना चाहिए।

विश्लेषकों के अनुसार, यह आंतरिक कलह बीजेपी के छत्रपति संभाजीनगर चुनाव प्रचार अभियान के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है यदि नाराज कार्यकर्ताओं की मांगों और गुस्से को समय पर शांत नहीं किया गया।

दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला: विशेष शालाओं में शिक्षक समायोजन के लिए एक माह की समय-सीमा तय, तुकाराम मुंढे की नई एसओपी लागू

मुंबई। दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा में निरंतरता, गुणवत्ता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने विशेष शालाओं और कार्यशालाओं में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के समायोजन को लेकर एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत अब शिक्षक समायोजन की पूरी प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

नई एसओपी के अनुसार, यदि किसी मान्यता प्राप्त विशेष शाला या कार्यशाला की मान्यता रद्द होती है और उस पर कोई न्यायालयीन स्थगन आदेश नहीं है, तो संबंधित संस्था को तत्काल बंद माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वहां कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को बेरोजगार न रखते हुए, नजदीकी विशेष शालाओं या संस्थानों में अस्थायी रूप से समायोजित किया जाएगा। समायोजन के दौरान पद की समानता और वेतनमान में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समायोजन प्रक्रिया में दिव्यांग कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए हर वर्ष नवंबर माह के पहले सप्ताह में और उसके बाद प्रत्येक माह अतिरिक्त कर्मचारियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सूची प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारियों को एक माह के भीतर समायोजन पूरा करना होगा।

यदि तय समय-सीमा में समायोजन नहीं किया गया या जानबूझकर टालमटोल की गई, तो संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं पर शिस्तभंगात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, समायोजन लंबित रहने तक नई भर्ती को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दिव्यांग कल्याण विभाग के अधिकारियों की होगी। तुकाराम मुंढे द्वारा जारी इस एसओपी को दिव्यांग शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और दूरगामी सुधारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)